अगले कुछ महीनों में सभी स्कूलों में शौचालय बना दिए जाएंगे - प्रधानमंत्री
15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्र को फीडबैक की प्रतीक्षा

विशेष लेख
स्वच्छ भारत

नीरज बाजपेयी

लालकिले के प्राचीन से दूसरी बार राष्ट्र को संबोधित करने से करीब 2 महीने पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सभी स्कूलों में कुछ ही महीनों में शौचालय उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पिछले वर्ष लालकिले के प्राचीर से ही प्रधानमंत्री ने 'स्वच्छ भारत' अभियान की घोषणा करते हुए एक वर्ष के भीतर प्रत्येक विद्यालय में शौचालय उपलब्ध कराने का वायदा किया था। हाल ही में युनाइटिड न्यूज आफ इंडिया (यूएनआई) के साथ एक साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि 'स्वच्छ भारत' मिशन के नतीजे सामने आने लगे हैं। इस अभियान में यह देखा जा रहा है कि गरीबों के स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी मुद्धो का दुष्प्रभाव उनकी क्षमता और उनके कार्य निष्पादन पर न पड़े। उन्होंने दावे के साथ कहा कि ''हमने सभी स्कूलों में शौचालय प्रदान करने का काम शुरू किया है। यह कार्य अगले कुछ महीनों में पूरा होने जा रहा है। क्या इन सार्वजनिक स्कूलों में गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं" श्री मोदी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि उनके विरोधियों का आरोप है कि श्री मोदी कॉर्पोरेट समर्थक, किसान विरोधी और गरीब विरोधी सरकार के प्रतिनिधि हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के अलावा उन्होंने सामान्यजन के लिए शुरू किए गए कई अन्य कार्यक्रमों का भी हवाला दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा ''ये कुछ उदाहरण हैं। पिछले 60 वर्षों के दौरान इन कार्यों को प्रभावकारी ढंग से पूरा किए जाने में क्या रुकावटें थीं" प्रत्येक परिवार में बच्चे अपने बुजुर्गों को यह स्मरण कराने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं कि स्वच्छता की शुरुआत घर से होनी चाहिए ''आपका प्रश्न इसी बात को रेखांकित कर रहा है, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि प्रत्येक नागरिक स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनने का निर्णय करता है, तो स्वच्छता स्वतः ही समूचे समाज में आ जाएगी, उन्होंने कहा कि ''यदि प्रत्येक नागरिक इसकी चिंता करेगा, तो हर जगह को स्वच्छ बनाया जा सकेगा''।

प्रधानमंत्री ने 2 अक्तूबर, 2014 को राजपथ पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। उसके बाद से इस अभियान को लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। कुछ स्थानों पर तो ऐसे सामाजिक संगठन भी इस अभियान में शामिल हो रहे हैं, जिनका शहर की स्वच्छता से कोई सरोकार नहीं है और अनेक समूहों को सार्वजनिक उद्यानों में बार बार मलबा साफ करते हुए

देखा जा सकता है। इस अभियान का लक्ष्य 2019 तक सभी 4041 सांविधिक शहरों में नगरीय क्षेत्रों को खुले में शौच जाने से मुक्त बनाना और उनमें स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इस काम पर 66,009 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 14,643 करोड़ रुपये की होगी।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों में 1.04 करोड़ घरेलू शौचालयों, 2.52 लाख सामुदायिक शौचालयों और 2.54 लाख सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और 30 करोड़ शहरी आबादी को ठोस कचरा प्रबंधन पद्धतियों में सहायता प्रदान करना शामिल है। 2014-15 के दौरान 28 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए करीब 800 करोड़ रुपये जारी किए गए। इस दौरान 2 लाख से अधिक घरेलू शौचालयों और 12 हजार सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 390 शहरों से रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने नगरीय ठोस कचरा शत-प्रतिशत इकट्ठा किया और उसका समुचित निपटान किया। सार्वजनिक सम्मेलनों और सभाओं के दौरान और उनके बाद स्वच्छता सुनिश्चित करने के बारे में सरकार द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी जारी की गईं। जब यूएनआई के संवाददाताओं ने देशभर में लोगों से बातचीत की तो ज्यादातर लोगों का यह कहना था ''भाई साहब, मोदी जी ने लालकिले पर बोला था स्वच्छता के बारे में, हम तो स्वतंत्रता दिवस पर उनके फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं''। समूचे देश में लोगों की प्रतिक्रिया और सोच एक जैसी थी लेकिन सभी ने यह माना कि स्वच्छता पर बल अवश्य दिया जा रहा है।

अब जबकि कुछ ही दिन शेष हैं जब श्री मोदी लालकिले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जहां से उन्होंने यह घोषणा की थी कि एक साल के भीतर सभी स्कूलों में शौचालय प्रदान करने का काम पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं कि सभी स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए। ''राज्य सरकारों की मदद से यह कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और अगले वर्ष 15 अगस्त को हम यह घोषणा करने की स्थिति में हों कि भारत में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है, जिसमें लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय न हों''।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बड़ी संख्या में सरकारी एजेंसियों के सहयोग से यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में प्रत्येक स्कूल में शौचालय हो। साथ ही, यह तैयारी भी चल रही है कि 14 जुलाई से 25 सितंबर की अवधि में गोदावरी नदी के किनारे नाशिक में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले के अवसर पर स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। हाल ही में इस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक में श्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कुंभ मेला और जगन्नाथ यात्रा जैसे प्रमुख धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान आध्यात्मिक नेताओं को स्वच्छता प्रयासों से जोड़ा जाना चाहिए। अगले वर्ष मध्य प्रदेश में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी के निर्देशों के बाद

अधिकारीगण नाशिक में मेले के अवसर पर अधिकतम ''स्वच्छता'' सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जहां पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अनेक लोगों का कहना है कि यह स्वच्छता अभियान की वास्तविक अग्नि परीक्षा है। श्री मोदी पहले ही सलाह दे चुके हैं कि अधिकतम स्वच्छता सुनिश्चित करने के लि धर्म गुरुओं की सहायता से लोगों में स्वच्छता के प्रति लोगों के नजरिए में बदलाव किया जाना चाहिए। कुंभ मेला एकमात्र अवसर नहीं है, बल्कि ऐसे ही तैयारी ओडिशा में पुरी धाम में जगन्नाथ यात्रा के धार्मिक कार्यक्रम के लिए की जा रही है।

कुंभ मेला महाराष्ट्र में नाशिक में त्रयंबकेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। त्रयंबकेश्वर नाशिक का एक पवित्र शहर है, जो 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक है, जहां त्रयंबकेश्वर ज्योर्तिलिंग मंदिर स्थित है। नाशिक में कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान ने एक माहौल तैयार किया है, जिससे यह मार्ग प्रश्स्त हो सकता है कि इस शब्द को अंग्रेजी कोश में शामिल कर लिया जाए, जिसमें बंगला, लूट, बंद और तूफान जैसे भारतीय शब्द पहले ही शामिल किए जा चुके हैं। स्वच्छ शब्द का इस्तेमाल अब इसी तरह किया जाने लगा है और इस शब्द ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है और अनेक बार इसके अनुवाद की अपेक्षा नहीं की जाती है।

अचरज की बात है कि सामान्य धारणा के अनुसार स्वच्छ का अर्थ हाइजीएनिक होता है, परंतु कुछ हल्कों में राजनीतिक अर्थ में इसे ''अनहाइजीएनिक'' की संज्ञा दी जा रही है। ऐसे लोग दावे के साथ कहते हैं कि यह सब सार्वजनिक दिखावा है, और इससे भी आगे बढ़ कर कुछ आलोचक अपनी बात पर जोर देने के लिए लुटियन्स जोन में भी मूत्र से सनी दीवारों की ओर संकेत करते हुए यह कहते हैं कि जब यहां ऐसा हाल है, तो देश के दूरदराज के मुफस्सिल क्षेत्रों की बात क्या करें। देशभर में सूचना-पट्ट, पोस्टर, स्टिकर दिखाई देते हैं और सरकारी तथा निजी संस्थान इस अभियान में शामिल हो गए हैं, परंतु सत्ता के गलियारों में नौकरशाह यह महसूस करते हैं कि सरकार ऐसे आंदोलनों के लिए मात्र एक सुविधा प्रदाता हो सकती है, जब तक लोग व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे, तब तक स्वच्छता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। श्री मोदी के अनुसार कि विभिन्न चैनलों से राष्ट्र को यह संदेश देने का काम शुरू किया गया है कि 'स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने का एक अवसर है और 2019 में उनकी 150 वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है।

'स्वच्छ भारत' कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इस बीच, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा कि यह कार्यक्रम सिर्फ स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि बुनियादी रूप में अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने से भी सम्बद्ध है। स्थानीय समाचार एजेंसी में कार्यरत एक वरिष्ठ पत्रकार जय प्रकाश अवस्थी के अनुसार, यदि सरकारी निकाय सार्वजनिक स्थलों पर समुचित संख्या में शौचालय उपलब्ध नहीं कराएंगे

तो यह अभियान विफल हो जाएगा। वे व्यंग्यात्मक ढंग से टिप्पणी करते हैं कि देश के सबसे पॉश लुटियन्स जोन में आईएनएस (इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी) परिसर में आने वाले ड्राइवर और आम लोग जिन्हें घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वे पेशाब करने के लिए बसों की ओट तलाश करते हैं। बस स्टैंडों पर जाइए और सार्वजनिक शौचालयों को देखिए तो आपको तत्काल यूरिनरी इन्फेक्शन (मूत्र संक्रमण) हो सकता है। जब तक इन स्थितियों का समाधान नहीं होता,तब तक यह मिशन कामयाब नहीं होगा''। कई अन्य आलोचक अधिकारियों पर आधे मन से काम करने का दोष लगाते हैं। उनका कहना है कि नई दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 साफ सुथरा है लेकिन ''अन्य प्लेटफार्मों की स्थिति क्या है''

आइए देखते हैं कि ''स्वच्छ'' शब्द से लोग क्या अर्थ निकालते हैं, वे सार्वजनिक स्थानों पर चूने की लकीरों और दीवारों पर लगे स्टिकरों और साथ में रखे गए कूड़ेदानों की ओर इशारा करते है, परंतु यही लोग खुले में शौच जाने वाले लोगों और बाजार स्थलों पर मूत्र से सनी दीवारों की ओर भी इशारा करते हैं। रेडियो पर जिंगलों के जरिए अभियान के लिए समर्थन जुटाया जाता है और जाने माने लोग सार्वजनिक मंचों पर स्वच्छता का संदेश देते हैं।

जब से यह अभियान जोर पकड़ने गा, तो अनेक ऐसी घटनाएं हुईं और महाराजगंज की प्रियंका भारती का मामला सुर्खियों में आया, जिससे कई तरह की बहस शुरू हुई। 19 वर्षीय दुल्हन ने शौचालय न होने के विरोध में पति का घर छोड़ दिया। उसे यह कहते हुए पाया गया कि ''मैंने दिनभर कुछ खाया-पीया नहीं ताकि निवृत्त होने के लिए खेत में न जाना पड़े। रात के समय खेत खतरनाक हो सकते हैं। इससे मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा जिसका मैंने विरोध किया''।

समाज ने प्रियंका पर ससुराल जाने के लिए दबाव डाला, लेकिन उसने अपना विरोध नहीं छोड़ा। इसके बाद सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में लगा एक सामाजिक संगठन आगे आया, जिसने उसके घर में शौचालय बनवाया। आज वह घरों में शौचालय बनाने और सफाई सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए व्यापक यात्राएं कर रही है।

इस संघर्ष में प्रियंका अकेली नहीं है। कर्नाटक के बेल्लारी तालुक में एक 32 वर्षीय व्यक्ति ने पिछले महीने अपनी शादी के कार्ड पर ''स्वच्छ भारत'' मिशन का संदेश छपवाया। इस कार्ड से यह संदेश प्रचारित करने में मदद मिली कि स्वस्थ जीवन के लिए घर में शौचालय बनाना जरूरी है। एक विशेष पहल के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों के 300 सरकारी इंटर कॉलेजों में सैनिटरी नेपकिन्स के निपटान के लिए इंसिनेरेटर्स लगाने के एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। सूत्रों के अनुसार यह कार्यक्रम 73 जिलों में कॉलेजों में शौचालय बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना का एक हिस्सा होगा, जिस पर करोड़ों रुपये की लागत आएगी। श्री मोदी ने हाल ही में शहरी विकास, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्रालयों, नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक में अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों में शौचालयों के निर्माण के बारे में अद्यतन जानकारी मांगी। स्थिति

की व्यापक समीक्षा करने के बाद प्रधानमंत्री ने सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन राज्यों के साथ विशेष रूप से समन्वय करें, जिनमें शौचालयों के निर्माण की प्रगति धीमी है। उन्होंने 'नमामि गंगे' कार्यक्रम से सम्बद्ध अधिकारियों से कहा कि गंगा नदी के किनारे स्थित बस्तियों में शौचालयों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सरकारी चैनलों के जरिए पुरस्कार देने जैसे प्रोत्साहक उपाय भी किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वच्छ भारत से प्रवासी भारतीयों में जो रुचि पैदा हुई है, उसका भी लाभ उठाया जाना चाहिए।

अब सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान बड़े पैमाने पर शौचालयों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में योगदान कर रहे हैं। इनमें कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, आरईसी, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन, पावर ग्रिड कार्पोरेशन, एनएचपीसी और ओएनजीसी शामिल हैं। निजी कार्पोरेट भी इस कार्य में जुट गए हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन 'स्वच्छ भारत कोष' स्थापित किया गया है ताकि अंशदान प्राप्त किया जा सके। इस कोष से स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम के लिए धन दिया जा रहा है। रेल डिब्बों में गंदे शौचालयों, कीटों और मच्छरों की शिकायतों को देखते हुए सफाई को लेकर रेलवे की आलोचना की जा रही है। रेल मंत्रालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। अधिकारियों का कहना है कि 2015-16 से गैर-वातानुकूलित सहित सभी नव-निर्मित डिब्बों में कूड़ेदान लगाने की व्यवस्था की जा रही है। मौजूदा डिब्बों में भी कचरा कम्पैक्टरों के अतिरिक्त कूड़ेदान लगाने की योजनाएं हैं। पर्यावरण और हाउसकीपिंग के लिए अलग निदेशालय बनाया जा रहा है और स्वच्छता के लिए एकीकृत नीति तैयार की जा रही है।

डिब्बों में बायो-शौचालय शुरू किए जा रहे हैं ताकि लाइनों पर खुले में मल विसर्जन की प्रणाली समाप्त की जा सके। मार्च महीने तक ऐसे 17000 से अधिक शौचालय लगाए जा चुके थे और 2015-16 में भी इतनी ही संख्या में शौचालय लगाए जाएंगे। दो ऐसे सेक्शनों की पहचान की गई है, जिनमें इस वर्ष 2 अक्तूबर तक ''शून्य शौचालय विसर्जन'' की व्यवस्था की जाएगी। ये हैं - कनालुस-स्वार्का-ओखला और पोरबंदर-वांसजालय। जम्मू-कटरा और मन्माडुरई-रामेश्वरम सेक्शनों को इस वर्ष बाद में कवर किया जाएगा। इन सेक्शनों में शुरू होने वाली और समाप्त होने वाली तथा उनसे गुजरने वाली सभी रेलगाड़ियों में बायो-शौचालय लगाए जाएंगे।